किशोरियों की आवाज़

दीपिका सिंह और नेहा पर्ती

यह लेख भारत के सात राज्यों की 12-16 वर्ष आयु-वर्ग की किशोरियों के साक्षात्कार पर आधारित है। ये किशोरियाँ स्कूल, आवासीय स्कूल और अनौपचारिक शिक्षण स्थानों जैसे सामुदायिक क्लबों में पढ़ती हैं। हमारा उद्देश्य यह समझना था कि कोविड-19 ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया है, ख़ासकर स्कूली शिक्षा, शिक्षा और अधिगम से सम्बन्धित पहलुओं को।

कोविड-19 और उसका प्रभाव

लड़कों की तुलना में, लड़कियों के लिए महामारी एक अलग रूप में सामने आई है। यूँ तो सबका जीवन निश्चित रूप से बदला ही है, लेकिन यह बदलाव सभी के लिए एक-सा नहीं है। इस समय में कुछ लोगों को परिवार के साथ अधिक समय बिताने और यू-ट्यूब से नई चीज़ें सीखने का अवसर मिला है, तो कुछ लोगों का पहले से ही कठिन जीवन और भी कठिन हो गया है। असम में एक लड़की अपने भाई और शराबी पिता के साथ रहती थी। पिता उसके साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करता था, जबकि वह घर का सारा काम करती थी। वहाँ आई बाढ़ के कारण ज़रूरी वस्तुओं तक उनकी पहुँच और कम हो गई थी। वह दमे की मरीज़ थी, इसलिए उसे इस बात की चिन्ता सताने लगी कि उसे दवाई कैसे मिलेगी। इसके विपरीत, कर्नाटक में संयुक्त परिवार में रहने वाली एक लड़की 24 घण्टे फ़ोन का उपयोग करती थी और उसे अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए परिवार का समर्थन प्राप्त था।

भविष्य के बारे में चिन्ता

इन सभी अनुभवों में कुछ बातें समान हैं जिन्हें साझा करना आवश्यक है। *'अगर स्कूल फिर से नहीं खुले तो हमारे सपने अधूरे रह जाएँगे,'* एक लड़की की कही यह बात, स्कूल जाने वाली सत्रह (85%) लड़कियों की बातों में भी प्रतिध्वनित हो रही थी। हमने यही बात फिर से तब सुनी जब हमने कुछ ऐसी लड़कियों (15%) के साथ बातचीत की, जिन्होंने कक्षा V और VII के बाद स्कूली शिक्षा बन्द कर दी थी, लेकिन एक युवा क्लब में आयोजित गतिविधियाँ उन्हें सार्थक लग रही थीं।

अलग-अलग लड़कियों के लिए भविष्य के सपनों का मतलब अलग-अलग था। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब था कंप्यूटर इंजीनियर, स्नायु विज्ञानी (न्यूरोलॉजिस्ट) या पुलिस अधिकारी बनने की अपनी आकांक्षाओं को आगे बढ़ा सकना। दूसरों के लिए इसका मतलब था फिर से खेल पाना; स्कूल में अपनी पढ़ाई जारी रखना; स्वतंत्र रूप से घूमना और अपने रिश्तेदारों जैसे दादी-नानी से मिल पाना।

दसवीं कक्षा की लड़कियाँ आगामी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में और स्कूल शुरू होने के बाद पाठ्यक्रम पूरा करने के बारे में चिन्तित थीं। उन सभी को प्रमोट कर दिया गया था और वे मानसिक रूप अगली कक्षा में जा चुकी थीं। वैसे उनमें से आठ (40%) के पास नई पाठ्यपुस्तकें नहीं थीं। वे पुरानी और माँगी हुई किताबों से काम चला रही थीं।

लगभग सभी लड़कियाँ अपने परिवार की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति और खाद्य आपूर्ति की अनिश्चितता को लेकर चिन्तित थीं। एक अभिभावक के पास तो भोजन के लिए भी पैसे नहीं थे। राशन के लिए वे अपने पड़ोसियों पर निर्भर थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन खरीदने के लिए पैसे उधार लिए ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। कुछ टिप्पणियाँ इस तरह थीं :

अभी तो खाने को है, कुछ दिनों बाद शायद न हो।

अभी तो पड़ोसी खाना दे रहे हैं - दाल, चावल, तेल...पर कितने दिन?

अपने शिक्षार्थियों को समझना

अपने शिक्षार्थियों को समझने से तात्पर्य है उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, सीखने की शैली व प्राथमिकताओं, सीखने की तत्परता और पिछले शैक्षिक प्रदर्शनों के बारे में अन्तर्दृष्टि प्राप्त करना। ओडिशा में एक लड़की ने शिक्षार्थियों की विविधता के बारे में बात करते हुए कहा : *सब सभी बच्चे एक जैसे तो नहीं सीखते, कुछ को ज़्यादा समय लगता है, उनकी पढ़ाई कैसे होगी इस समय?*

प्रौद्योगिकी के साथ सम्बन्ध

इस महामारी ने जो नए आयाम जोड़े हैं वे अधिगम के प्रासंगिक अनुभवों को डिज़ाइन करने में महत्त्वपूर्ण हैं। डिजिटल अधिगम के लिए ज़रूरी व्यवहार भी उतना ही महत्त्वपूर्ण हो गया है जितना कि प्रौद्योगिकी तक पहुँच और इसका प्रयोग आसानी

से कर पाना। जब प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अधिगम-अनुभवों को डिज़ाइन करना हो तो जिन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, वे इस प्रकार हैं - प्रौद्योगिकी के साथ पूर्व-सम्पर्क, सहपाठियों के नेटवर्क के साथ जुड़ना तथा शिक्षार्थी और उसके परिवार का दृष्टिकोण।

लड़कियों के लिए प्रौद्योगिकी तक पहुँच हमेशा ही एक समझौते वाली बात होती है, फिर चाहे वह अभिभावकों के साथ हो या भाई-बहन के साथ। अभिभावकों से मिलने वाले समर्थन में अन्तर होता है। यहाँ पहले उदाहरण में, लड़की अपने पिता की आभारी है कि उन्होंने फ़ोन लाकर दिया, *'पापा ने लोन लेकर फ़ोन ला कर दिया, ताकि मैं पढ़ाई कर सकूँ।'* दूसरी ओर, एक अन्य लड़की फ़ोन पर अपनी सीमित पहुँच की बात करती है, *'अगर मैं ज़्यादा टाइम फ़ोन पर होती हूँ तो पापा गुस्सा करते हैं ।'*

फ़ोन की उपलब्धता पहली चुनौती है। अपने अध्ययन में हमने देखा कि ज़्यादातर लड़कियों के घर में एक ही फ़ोन था जिसे साझा करना होता था। अब किसे पहले फ़ोन मिले और कितनी देर के लिए मिले – यह निर्णय बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है। चौदह लड़कियों ने कहा कि उनके घर में स्मार्टफ़ोन है। इनमें से चार लड़कियाँ दिन में केवल एक घण्टे या उससे कम समय के लिए फ़ोन का इस्तेमाल कर पाती थीं। कुछ केवल दो या तीन घण्टे के लिए और एक लड़की ने तो कहा कि, *'फ़ोन भाई के पास रहता है पूरा दिन।'*

कुछ अन्य मुद्दे भी थे। बिहार में जब हमारे सुगमकर्ताओं ने लड़कियों को सीखने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए *व्हाट्सएप* समूह बनाने शुरू किए तो एक अभिभावक ने उनसे कहा कि उनकी बेटी केवल लड़कियों के समूह में ही भाग ले सकती है। अभिभावकों द्वारा *व्हाट्सएप* समूहों को जेंडर सम्बन्धी मानदण्डों से प्रभावित करना, लड़कों के साथ बातचीत को नियन्त्रित करने के बारे में अनकहे सरोकारों को दर्शाते हैं। प्रचलित जेंडर मानदण्ड प्रौद्योगिकी-संचालित प्रक्रिया में एक नया रूप लेते हैं। लड़कियों को न केवल अपने बड़े भाई-बहनों और पिता के साथ फ़ोन का उपयोग करने के लिए समय निकालने के लिए समझौते करने पड़े, बल्कि घर के कामों को भी फ़ोन की उपलब्धता के अनुसार व्यवस्थित करना पड़ा। और फिर, फ़ोन मिलने मात्र से यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि उनमें उसका उपयोग करने का विश्वास भी है। एक लड़की ने यह बात मानी कि उसने फोन के उन बटनों को नहीं दबाया जिनके बारे में उसे पता नहीं था।

अभी तक इन उपकरणों को मुख्य रूप से मनोरंजन के स्रोतों के रूप में देखा जाता था। उनका उपयोग संगीत सुनने, कहानियों को पढ़ने, कला व क्राफ्ट सम्बन्धी वीडियो देखने या गेम खेलने के लिए किया जाता था। लेकिन लॉकडाउन के दौरान क़रीब 50 प्रतिशत लड़कियों ने *यू-ट्यूब* का उपयोग करके कुछ नया सीखा था। दिलचस्प बात यह थी कि इन गतिविधियों में विद्यार्थियों ने स्व-अधिगम प्रदर्शित किया, लेकिन अकादमिक विषयों में ऐसा नहीं था, उसके लिए वे किसी-न-किसी वयस्क पर निर्भर रहते थे।

विश्वास

गुजरात में एक लड़की ने इस मुद्दे को उठाया जो आजकल चल रहे ऑनलाइन अधिगम के लिए महत्त्वपूर्ण है :

'किस पर विश्वास करना है और किस पर विश्वास नहीं करना है, यह कैसे पता चलेगा ऑनलाइन?' इससे पता चलता है कि लोगों को, विशेष रूप से युवा लड़कियों को, डिजिटल मंच और उसमें अपनी सुरक्षा करने के बारे में तैयार नहीं किया गया है। पाठ्यचर्या के निष्पादन Curriculum transaction) के साथ-साथ लड़कियों और उनके माता-पिता को इस मंच पर लाने के लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाने की ज़रूरत है।

प्रौद्योगिकी और अधिगम

लड़कियाँ अपने सीखने के सम्बन्ध में मिलने वाले फ़ीडबैक को याद करती हैं क्योंकि अब उनके लिए यह जानना कठिन है कि वे सही रास्ते पर हैं या नहीं। यह बात *प्रमाणीकरण की आवश्यकता* को पुष्ट करती है जो हमारी शिक्षा प्रणाली में अन्तर्निहित है। स्व-अधिगम के लिए आत्मविश्वास की भावना का विकास नहीं किया गया है। जैसे-जैसे हम प्रौद्योगिकी-सक्षम अधिगम की ओर बढ़ते हैं, आकलन और सीखने की प्रकृति को बदलने के लिए अपनी मानसिकता में बदलाव लाना भी ज़रूरी है।

शिक्षकों को यह समझना होगा कि शिक्षार्थियों की चिन्ता का कारण क्या है और प्रौद्योगिकी कैसे इसमें योगदान करती है। विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जहाँ न तो शिक्षार्थी और न ही शिक्षक इसके लिए तैयार थे। उदाहरण के लिए एक लड़की ने कहा कि उसके शिक्षक व्हाट्सएप पर कोई आलेख भेजते हैं और यदि वह उसे समझने में असमर्थ हो तो वे अवधारणा को समझाने के लिए एक वीडियो भेजते हैं। इस प्रकार सीखने की जाँच करने के लिए कोई तात्कालिक फ़ीडबैक नहीं है।

यहाँ महत्त्वपूर्ण कारक यह हैं कि अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त है, अवधारणा के व्यावहारिक रूप को देखने के लिए उसका अनुप्रयोग तत्काल नहीं होता और सिद्धान्त पर अधिक ध्यान देने को ही अधिगम का तरीक़ा माना जाता है। कुछ लड़कियों ने कहा कि अपने आप या व्हाट्सएप-आधारित अन्त:क्रियाओं के माध्यम से विज्ञान और गणित सीखने में

उन्हें कठिनाई होती है। यह व्यवहार और अपेक्षाएँ, स्वयं अपनी रुचि से कुछ सीखने और स्व-अधिगम का प्रदर्शन करने के विपरीत हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था।

अभिभावकों की भूमिका

इस अध्ययन में शामिल लड़कियों के परिवारों में स्मार्टफ़ोन, फीचर फ़ोन और टेलीविज़न सेट जैसे उपकरण साझा किए जाते थे। केवल एक लड़की के पास अपना फ़ोन था। फ़ोन का उपयोग ज़्यादातर पिता द्वारा किया जाता था और लड़कियों को यह केवल कुछ ही समय के लिए मिल पाता था, वह भी तब जब पिता घर पर हों। अगर घर पर टीवी था भी, तो उसका उपयोग ज़्यादातर मनोरंजन के लिए किया जाता था, शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए नहीं।

यद्यपि ऑनलाइन कक्षाओं में अभिभावकों की भागीदारी बहुत कम होती है, तो भी माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों, यहाँ तक कि पड़ोसियों ने भी बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में बहुत सहयोग दिया, उन्हें सीखने के लिए प्रोत्साहित किया और उनका समर्थन किया। इसके बावजूद सभी लड़कियों ने महसूस किया कि अपनी शंकाओं के निवारण के लिए या गणित की समस्याओं को समझने के लिए शिक्षकों के साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, जो दर्शाता है कि अधिगम के लिए पुनरावृत्ति कितनी महत्त्वपूर्ण है।

कई अभिभावकों ने पहली बार *व्हाट्सएप* समूह का उपयोग देखा। उन्हें यह देखने का अवसर मिला कि उनके बच्चे के साथ क्या साझा किया जा रहा है और किस तरह की चर्चा की जा रही है। यह सम्भावित नियंत्रण है : अभिभावक चाहते हैं कि बेटियाँ स्कूल के 'नियमित' विषय सीखें। पितृसत्तात्मक भारतीय पुरुष नहीं चाहते कि उनकी बेटी सवाल करे, आलोचना करे या अपने अधिकारों, शारीरिक अखण्डता (Bodily Integrity) और इस तरह के अन्य विषयों के बारे में जानें। यदि किशोरों के साथ काम करने वाले संगठन ऐसी सामग्री को साझा करने का प्रयास करते हैं तो बहुत सम्भव है कि अभिभावक प्रतिरोध करें और तीखी प्रतिक्रिया दिखाएँ और राज्य इस बात से अवगत है।

शिक्षकों की भूमिका

युवा शिक्षार्थियों के जीवन में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। वे उनके भविष्य की परवाह करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं और उनकी सहायता करते हैं। जिन बीस किशोरियों से हमने बातचीत की, वे सभी सरकारी स्कूलों में नामांकित थीं या शिक्षण के अनौपचारिक स्थानों की सदस्य थीं, जैसे गाँव के युवा क्लब। शिक्षक और समकक्ष शिक्षक बहुत प्रभावकारी होते हैं, जिनसे वे अपनी शंकाओं के बारे में पूछते हैं या उनसे बात करते हैं। लगभग सभी साक्षात्कारों में लड़कियों ने कहा कि वे अपने शिक्षकों के प्रोत्साहन को बहुत याद करती हैं, किसी विशेष विषय को समझने के लिए कक्षा में उन तक पहुँचना कितना आसान था। लेकिन केवल 25 प्रतिशत लड़कियों ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों ने उनसे सम्पर्क किया, जो कि मुख्यतः फ़ोन कॉल और *व्हाट्सएप* के माध्यम से किया गया।

शिक्षकों को तैयार करना

ऐसे समय में, जब हर कोई दूरस्थ शिक्षा के साथ प्रयोग कर रहा है, तो शिक्षकों को पाठ-योजना बनाने से पहले अपने शिक्षार्थियों को अच्छी तरह से समझने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण में कई आयामों को शामिल करना चाहिए - विद्यार्थियों की भलाई, विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन सीखने के आधार तैयार करना, माता-पिता को तैयार करना, डिजिटल सुरक्षा का ध्यान रखना और शिक्षार्थियों को अधिगम-अनुभव प्रदान करने के इस नए तरीक़े के साथ शिक्षकों का स्वयं सहज होना। प्रशिक्षण में विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप को शामिल करना चाहिए ताकि उनकी चिन्ताओं को समझकर उन्हें वह समर्थन दिया जा सके जिसकी ज़रूरत उन्हें इस प्रकार के आभासी (वर्चुअल) अधिगम के लिए पड़ती है। इसका अर्थ है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों तक पहुँचने के लिए विभेदित रणनीतियों से लैस करना होगा, उदाहरण के लिए, एकीकृत *वॉयस रिस्पांस सिस्टम, व्हाट्सएप* और *टेलीकांफ्रेंसिंग* का उपयोग करना।

शिक्षकों को भी पाठ्यक्रम को फिर से तैयार करने और उसे विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए संवाद स्थापित करने के बारे में चिन्ता हो सकती है। राज्य द्वारा उन्हें पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए।

कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे

आगामी शैक्षिक वर्ष की परीक्षा के बारे में विद्यार्थियों के मन में काफ़ी चिन्ताएँ हैं, अतः उनके मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी महत्त्वपूर्ण है। उनमें से कई, ट्यूशन कक्षाओं में फिर से जाने लगे थे और पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता एक मुद्दा था। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में सामग्री को रेडियो या टीवी के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रसारित किया गया है। हमारे अध्ययन में शामिल अधिकांश लड़कियाँ संगीत और मनोरंजन के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर रही थीं। शैक्षिक साधन के रूप में रेडियो ने अपनी प्रासंगिकता खो दी है, इसलिए सरकार को यह देखना चाहिए कि रेडियो सत्र में शिक्षार्थी उन्हें सुन भी रहे हैं या नहीं।

टेलीविज़न की अलग समस्याएँ हैं। एक तो, हर घर में टीवी

सेट नहीं है, दूसरे लड़कियों को घर के कई काम करने पड़ते हैं। तो हो सकता है कि जब पाठ स्ट्रीम किए जाते हैं, उस समय उन्हें टीवी देखने की फ़ुर्सत न हो। ओडिशा की एक लड़की के शब्दों में, *"अभी तो 20 प्रतिशत बच्चे ही इससे जुड़ पा रहे हैं, बाक़ी का क्या?"*

यह सोचना अव्यावहारिक होगा कि ऑडियो या वीडियो पाठ प्रसारित करने और *व्हाट्सएप* पर पाठ साझा करने से शिक्षार्थियों को अवधारणाओं की समझ मिल ही जाएगी। जब वे वर्चुअल या आभासी साधनों के ज़रिए पढ़ाई करते हैं तो वह अधिगम का समग्र वातावरण नहीं होता। हो सकता है कि उनके आस-पास कोई वयस्क हो या न हो या उनके पास बच्चों के सन्देह दूर करने का समय न हो या वैसा करने के लिए उनके पास अपना निजी स्थान न हो। लड़कियों के लिए यह और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि उन्हें हमेशा घर के कामों के लिए बुला लिया जाता है और उनकी ज़रूरतें अधूरी ही रह जाती हैं ।

राज्य को चाहिए वह केवल तात्कालिक सरोकारों का जवाब देने की बजाय एक व्यापक योजना के साथ सामने आए। कुछ प्रमुख विचारणीय पहलू यह हैं :

- शैक्षिक वर्ष की अवधि और अधिगम की प्राथमिकताएँ क्या होंगी?
- महामारी के बारे में इतनी अनिश्चितता को देखते हुए, अगले कुछ वर्षों के लिए क्या योजनाएँ हैं?
- क्या परीक्षाएँ हमेशा की तरह आयोजित की जाएँगी, या उनमें परिवर्तन आएगा या वे रद्द कर दी जाएँगी?

चूँकि आकलन का अर्थ परीक्षा नहीं है, इसलिए नए तरीक़ों के बारे में सोचा जा सकता है। हमारी बातचीत से यह बात उभरी है कि हमारे कई उत्तरदाताओं को महामारी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो क्या शिक्षा के इन कार्यक्रमों में पाठ्यक्रम के बाहर के विषयों को शामिल किया जा सकता है? राज्य द्वारा इस तरह के प्रमुख निर्णय और शिक्षार्थियों तक इसका सम्प्रेषण बहुत सारी चिन्ताओं को कम कर सकता है। जिन युवा शिक्षार्थियों की पहुँच, वेब और तकनीकी-उपकरणों तक है, उन्हें संचालन और सुरक्षा-कौशलों से लैस करना महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

भारत के सरकारी स्कूलों में मानव संसाधन, बुनियादी संरचना और अधिगम के संसाधन अपर्याप्त हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया एक उपेक्षित क्षेत्र रही है। वर्तमान में भारत के पास राज्यों को बताने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश या नीति नहीं हैं जो इस प्रकार की आपात स्थिति में शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने डिजिटल लर्निंग (डिजिटल पुस्तकालयों) की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है पर डिजिटल विभाजन को कम करने की दिशा में आगे कैसे बढ़ना है यह स्पष्ट नहीं है।

हमारे अध्ययन में शामिल लड़कियों के लिए इन मुद्दों का बहुत महत्त्व है। वे अपने स्कूल, शिक्षकों और दोस्तों, सौहार्दपूर्ण गपशप, खेल, कन्धे पर वह हल्की-सी थपकी, इन सभी की कमी महसूस करती हैं; ज़रूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों तक पहुँच पाने की सम्भावना – यह सारी बातें लड़कियों की शिक्षा के बारे में सरोकार रखने वाले लोगों के लिए बहुत ही सकारात्मक संकेत हैं। लगभग सभी, लॉकडाउन के दौरान कुछ-न-कुछ सीख रही थीं, भले ही उनके घर पर कोई टीवी या स्मार्टफ़ोन हो या न हो। जैसे वे साइकिल चलाना सीख रही थीं, नए हेयर स्टाइल बनाना सीख रही थीं, लिखावट में सुधार कर रही थीं, पिछली कक्षा के गणित, व्याकरण या चित्रकारी में सुधार लाने के प्रयास कर रही थीं। सीखने की उनकी इच्छा बहुत स्पष्ट है और वे चाहती हैं कि स्कूल (शौचालय की बेहतर सुविधाओं के साथ), खेल के मैदान और मूलभूत व्यवस्थाएँ फिर से खुलें। इबोला जैसी पिछली महामारी के अनुभव बताते हैं कि शायद लड़कियाँ स्कूल में वापस न लौटें; शायद और अधिक लड़कियों की शादी कम उम्र में कर दी जाएगी। वास्तव में यह बात राज्य और नागरिक समाज के संगठनों पर निर्भर है कि वे किशोरियों की आकांक्षाओं को पंख दें और उनका समर्थन करें ताकि वे स्कूल और युवा क्लब जैसे शिक्षण स्थानों में फिर से शामिल हो सकें।

माता-पिता, परिवारों और समुदाय के सदस्यों की भूमिका को समझने की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका और खाद्य-असुरक्षा के कारण अभिभावकों के दृष्टिकोण में भी बदलाव आ रहा है। इस बात पर सोच-विचार करना होगा कि किशोरवय की लड़कियों की शिक्षा को जारी रखने में उन्हें कैसे सहयोगी बनाया जाए। इन लड़कियों के जीवन में शिक्षकों की भूमिका भी बहुत महत्त्वपूर्ण है और उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सामान्यतः, ग़ैर-सरकारी संगठनों और सरकार के बीच में स्कूलों की भूमिका, इसके बदलते हुए रूप और इसमें हो रहे परिवर्तनों के बारे में चर्चा होती है। अब परिवारों की भूमिका पर चर्चा करने की आवश्यकता है : परिवार सीखने की सुरक्षित जगह कैसे प्रदान कर सकते हैं, उन्हें ऐसा करने में कैसे समर्थन दिया जा सकता है और उनके दृष्टिकोण में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। इन सभी बातों को उस नैरेटिव का हिस्सा बनना चाहिए जिसका निर्माण एक ऐसे समय में हो रहा है जब हम कोविड-19 महामारी के बीच शैक्षिक संकट से निपटने के लिए तैयार हो रहे हैं।

यह तो स्पष्ट है कि सीखना जारी है। शिक्षार्थी सीमित संसाधनों

के साथ ही सही, लेकिन अपने विकल्प चुन रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं कि वे क्या सीखना चाहते हैं और कैसे सीखना चाहते हैं। राज्य और ग़ैर-सरकारी संगठनों को चाहिए कि वे इन सभी को सीखने के रूप में मान्यता दें। इसके अलावा, हम सभी लोग जो अधिगम और शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उन्हें इस बात में सक्षम होना चाहिए कि मानवीय सरोकारों को बरक़रार रखते हुए, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता सहित विविध शिक्षण-संसाधनों की मदद से, विविध प्रकार के शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न समाधानों को डिज़ाइन कर सकें।

दीपिका सिंह क्वेस्ट एलायंस के प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम आनन्दशाला में शिक्षा विशेषज्ञ हैं। उन्हें सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने पर केन्द्रित बड़े स्तर के शिक्षा कार्यक्रमों में एक दशक से अधिक का अनुभव है। दीपिका, शिक्षा को अधिक प्रासंगिक बनाने और शिक्षा में समता और समावेशन के मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन, सामग्री विकास, क्षमता निर्माण और एड-टेक के उपयोग के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती हैं। उनसे **Singh-deepika@questalliance.net** पर सम्पर्क किया जा सकता है।

नेहा पर्ती, क्वेस्ट एलायंस में सेकेण्डरी स्कूल प्रोग्राम की एसोसिएट डायरेक्टर हैं। नेहा शिक्षार्थियों के लिए 21 वीं सदी के कौशल और वैज्ञानिक मानसिकता के निर्माण पर केन्द्रित शैक्षिक कार्यक्रमों को डिज़ाइन करने के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। वे वर्तमान में एक ऐसे कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही हैं जो किशोरवय की लड़कियों को समकालीन कौशल में सशक्त बनाता है और स्व-अधिगम के लिए प्रमुख व्यवहारों का निर्माण करता है। उनसे **neha@questalliance.net** पर सम्पर्क किया जा सकता है। **अनुवाद :** नलिनी रावल